तेज संवृद्धि की सहायता: बैंकिंग क्षेत्र और वास्तविक क्षेत्र के बीच संबंध *

के.सी.चक्रवर्ती

प्रस्तावना

श्री राजकुमार धूत, माननीय संसद सदस्य और अध्यक्ष, एसोचॅम, श्री एम.नरेंद्र, अध्यक्ष, एसोचॅम राष्ट्रीय बैंकिंग और वित्त परिषद और सीएमडी, इंडियन ओवरसीज बैंक, श्री सुनील कनोरिया, उपाध्यक्ष, एसोचॅम और उपाध्यक्ष, एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनान्स लिमि; श्रीमती शुभदा राव, वरिष्ठ अध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री, येस बैंक लिमि.; श्री सुभाष सी. अग्रवाल, सीएमडी, एसएमसी समूह; सुश्री सुधा रवि, सह-अध्यक्ष, एसोचॅम राष्ट्रीय बैंकिंग और वित्त परिषद और सीईओ, पीएचएल फाइनान्स लिमि., श्री डी.एस.रावत, महा सचिव, एसोचॅम, प्रतिष्ठित अतिथि, देवियो और सज्जनो। एसोचॅम द्वारा "तेज संवृद्धि के लिए संतुलन" विषय पर आयोजित 8 वें वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन में उपस्थित रहना खुशी और सम्मान की बात है।

वर्तमान परिदृष्य

2. 90 के दशक के व्यापक संरचनात्मक सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ समय पहले तक प्रभावी वृद्धि दर दर्शा रही थी और अब इसका शुमार एक ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक जीडीपी वाले विशेष देशों के समूह में हो गया है। किंतु अब अनेक लोग वैश्विक अर्थव्यवस्था की चिंताजनक भावी तस्वीर पेश कर रहे हैं जिससे अर्थव्यवस्था संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं, अत: यह जरूरी हो गया है कि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावना की सूक्ष्म समीक्षा करके यह देखा जाए कि भारतीय वृद्धि की निरंतरता बनाए रखने के लिए किस बात की आवश्यकता है।

3. अर्थव्यवस्था में नरमी आने की बात कहने वालों का अनुमान आधरहीन नहीं है क्योंकि यूरोजोन एक बार फिर से मंदी की ओर बढ़ रहा है और ऋण संकट दक्षिणी यूरोप को निरंतर परेशान कर रहा है और यह निर्यात-प्रमुख जर्मनी के निष्पादन को प्रभावित कर रहा है। अमरीका में सुधार की संभावना से उत्साह है वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी की दर निरुत्साहजनक है और वहां राजकोषीय समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देशी स्थिति यह है कि वृद्धि की दर धीमी होने के कारण यहां भी संकट के कुछ बादल छाए होने के बावजूद वृद्धि की दर अभी भी विकसित देशों की तुलना में बेहतर है। भारत पर वैश्विक आर्थिक संकट का विशेष परिणाम नहीं हुआ जिसका कारण मजबूत विनियमन और पर्यवेक्षण तथा अपनाई गई प्रतिचक्रीय नीति का संयुक्त रूप था जो कि हमारे देश, समाज और संस्कृति के अनुकूल था। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम वैश्विक आर्थिक संकट से पूर्णत: बच गए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार के समय से निरंतर वृद्धि कर रही थी और संकट के पहले इसने 9 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की थी जो कि 2012-13 की पहली तिमाही में कम होकर 5.5 प्रतिशत रह गई और अनुमानित वृद्धि दर में अनुक्रमिक अधोमुखी सुधार करना पड़ा। यह दर अब बढ़ कर 2012-13 में 5.8 प्रतिशत होने का अनुमान है। किंतु यह स्तर हमारी वास्तविक क्षमता से बहुत कम है।

4. आर्थिक उदारीकरण के साथ हम "वृद्धि की हिंदू दर", जो कि 1950-80 के दौरान लगभग 3.5 प्रतिशत पर रुक गई थी, से काफी आगे आ गए हैं। दुन एंड ब्राडस्ट्रीट की "भारत 2020" नामक रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक भारत 5.6 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उक्त रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2020 तक महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों में शामिल होंगे और समग्र जीडीपी में इनका संयुक्त योगदान 32 प्रतिशत होगा। यह भी आशा है कि अब तक पीछे रह जाने वाले मध्य प्रदेश, बिहार, ओडीशा, राजस्थान

* एसोचॅम द्वारा नई दिल्ली में 21 नवंबर 2012 को आयोजित 8 वें वार्षिक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में डॉ.के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया मुख्य भाषण। इस भाषण को तैयार करने में श्रीमती थेरेसा करुणागरन से प्राप्त सहयोग के लिए उन्हें हार्दिक धन्यवाद।

और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी चालू दशक के दौरान भारत की वृद्धि गाथा में महत्त्वपूर्ण योगदान करेंगे।

5. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में तेज और अधिक समावेशक वृद्धि पर बल दिया गया। लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए आय और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और गरीबी कम करने तथा समावेशकता को बढ़ाने पर लक्ष्यित सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने की दृष्टि से 9.0 प्रतिशत वार्षिक की तेज जीडीपी वृद्धि का लक्ष्य आवश्यक समझा गया। वृद्धि के संदर्भ में अर्थव्यवस्था का निष्पादन अच्छा रहा और पहले चार वर्षों में इसका औसत 8.2 प्रतिशत रहा। ग्यारहवीं योजना के अंतिम वर्ष अर्थात 2011-12 में वृद्धि का लक्ष्य 9.0 प्रतिशत था किंतु यह संकट से उबरते हुए 6.5 प्रतिशत रही। पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 में अर्थव्यवस्था की मंदी सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं जैसी ही थी।

6. निसंदेह, वृद्धि में कमी आई है जिसका एकमात्र कारण वैश्विक मंदी को नहीं कहा जा सकता। इसका एक कारण देशी इंफ्रास्ट्रक्चर और अभिशासन के मुद्दों में देखा जा सकता है। दोहरा घाटा, मुद्रास्फीति और आपूर्ति पक्षीय बाधाएं कुछ ऐसी चिंताएं हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वृद्धि को तेज किया जा सके। भारत के सामने अब यह चुनौती है कि क्या वृद्धि की हिंदू दर की ओर पुन: लौटना और हमेशा के लिए एक विकासशील देश कहलाना हमारे लिए ठीक होगा या हमें विश्व के प्रमुख देशों के बीच अपना उचित स्थान पाने के लिए प्रयास करने चाहिए? अब हम वृद्धि की हिंदू दर की ओर न तो लौट सकते हैं और न ही हमें लौटना चाहिए।

7. इन चुनौतियों से पार पाने के लिए उत्पादकता, नवोन्मेष और सुधार के प्रमुख क्षेत्रों पर समष्टि आर्थिक और निजी फर्म/ उद्यम स्तर पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसकी सहायता से हम वृद्धि को प्रभावित करने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर कर सकते हैं और सुदृढ़ उच्च आर्थिक वृद्धि के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि एक पोषक वातावरण की निर्मिती के लिए हम अपनी शक्ति बढ़ा पाएंगे जिसके संबंध में मैं आगे उल्लेख करूंगा। इन सुधारों में सभी पणधारियों को शामिल किया जाना चाहिए और यह भी आवश्यक है कि प्रौद्योगिकी का पूरा लाभ लिया जाए क्योंकि इसमें उत्पादकता, नवोन्मेष और सुधार संबंधी हमारे प्रयासों को प्रभावी बनाने का सामर्थ्य है। इनमें से कुछ मुद्दों पर आज के अन्य तकनीकी सत्रों में अधिक चर्चा होगी। मुझे विश्वास है कि इन सत्रों में इस बात पर व्यापक चर्चा होगी कि विभिन्न उपायों को प्रभावी और समयबद्ध तरीके से किस प्रकार लागू किया जा सकता है।

8. किसी भी अर्थव्यवस्था में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका वास्तविक अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पूरी करने की होती है। इसलिए यदि भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी पूरी क्षमता का लाभ लेना है तो वित्तीय क्षेत्र को इसमें मुख्य भूमिका निभानी होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा वित्तीय क्षेत्र मुख्य रूप से बैंक केंद्रित है और इसीलिए बैंकिंग क्षेत्र के कार्य निष्पादन का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के बाद से भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने एक लंबा रास्ता तय किया है जिसमें बैंकों ने पिछले दो दशकों में अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उदारीकरण से बैंकों को कारोबारी निर्णय लेने की अधिक स्वायत्तता मिली है किंतु साथ ही यह दायित्व भी मिला है कि वे अपना कारोबार कंपनी अभिशासन, ग्राहक सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्धता के साथ करें जिसमें वित्तीय समावेशन भी शामिल है।

9. मुझे इस संबंध में कोई संदेह नहीं है कि यदि आर्थिक वृद्धि में तेजी लानी है तो बैंक ही इसके प्रमुख प्रेरक होंगे। भारत में बेंकिंग क्षेत्र द्वारा दिया गया देशी ऋण हमारे जैसे उभरते एशियाई देशों की तुलना में बहुत कम है, उन्नत देशों की बात तो बहुत दूर की है। बैंकों के पास अब तक औपचारिक ऋण से दूर रहे क्षेत्रों में कारोबार बढ़ाने का व्यापक अवसर है।

10. बैंकों को लंबे समय तक उच्च वृद्धि स्तर बनाए रखने की क्षमता विकसित करनी होगी। उन्हें वास्तविक क्षेत्र के साथ भी मजबूत संबंध जोड़ने होंगे। इन संबंधों में प्रस्तावित उत्पादों और सेवाओं का प्रकार, मूल्यन रणनीति, अपनाए गए सुपुर्दगी माध्यम, वे क्षेत्र/उप क्षेत्र जिनपर ध्यान केंद्रित किया गया है, अपनाए गए प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म्स आदि सहित बैंकिंग परिचालनों के सभी पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। वास्तविक क्षेत्र के साथ इस संबंध से आर्थिक प्रणाली में बैंकों की मुख्य स्तंभ के रूप में संगतता सुनिश्चित होगी और वे राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करके कि वित्तीय

जीडीपी की तुलना में बैंकिंग क्षेत्र का देशी ऋण (% में)

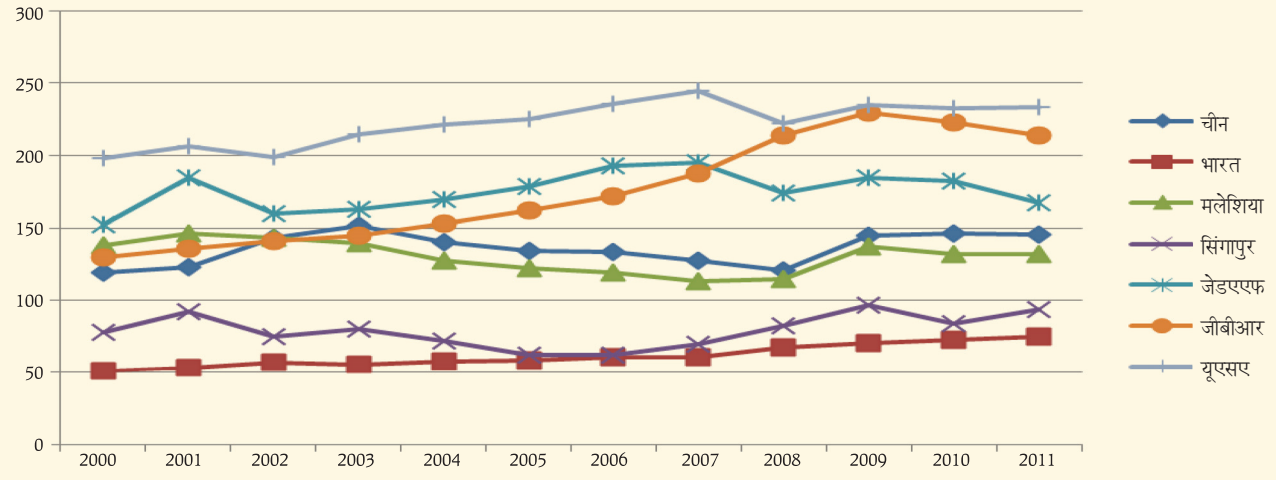

स्रोत: विश्व बैंक डाटा।

प्रणाली की वृद्धि वास्तविक क्षेत्र के अनुरूप है, आस्ति मूल्य के बुलबुलों से होने वाले प्रणालीगत जोखिम से बचा जा सकता है। वित्तीय प्रणाली और वास्तविक क्षेत्र के बीच लिंकेज की यह कमी वैश्विक वित्तीय संकट के अनेक कारकों में से एक महत्त्वपूर्ण कारक था और इसीलिए इस लिंकेज का महत्त्व जान लेना संकट से प्राप्त एक महत्त्वपूर्ण सीख है।

हमारी शक्तियां

जनसांख्यिकीय लाभ

11. कभी-कभी पौराणिक हनुमान जैसे ही हमें भी अपनी शक्तियों का स्मरण कराना होता है जिसमें हमारे देश में उपलब्ध बड़ा लाभ जनसांख्यिकी का है। हमारे देश में युवाओं की संख्या न केवल उन्नत अर्थव्यवस्थाओं बल्कि बड़े विकासशील देशों की तुलना में भी अधिक है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के एप्रोच दस्तावेज के अनुसार अगले 20 वर्षों में भारत की श्रम क्षमता में 32 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है जबकि औद्योगिक देशों में यह 4 प्रतिशत और चीन में लगभग 5 प्रतिशत कम होने की संभावना है। इस 'जनसांख्यिकीय लाभ' से सुदृढ़ दीर्घकालिक वृद्धि प्राप्त की जा सकती है जिसके लिए दो शर्तें पूरी की जाएं। एक, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास का उच्च स्तर प्राप्त किया जाए। दो, एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाए जिसमें अर्थव्यवस्था न सिर्फ तेजी से बढ़े बल्कि युवाओं की आवश्यकताएं और महत्त्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार/आजीविका के अवसर निर्माण करके समावेशन को भी प्रोत्साहन दे। जनसांख्यिकीय लाभ में कुशल, प्रौद्योगिकी की जानकारीयुक्त कार्य बल, मजबूत ग्राहक आधार और उच्च बचत दर निर्माण करने की क्षमता है जिससे उत्पादक निवेश के लिए उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि की जा सकती है। शिक्षा और साक्षरता के संबंध में हुई प्रगति से हमारी स्थिति विश्व के बॅक ऑफिस से बदलकर ज्ञान के सहयोगी के रूप में हो रही है।

समावेशक वृद्धि की क्षमता

12. रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के ग्राहकों की प्रोफाइल के संबंध में हाल ही में किए गए आंतरिक अध्ययन से आश्चर्यजनक बातें सामने आयी हैं। बैंक शाखाओं की बढ़ती संख्या के साथ प्रति बैंक शाखा औसत जनसंख्या 2001 के 15,583 से सुधरकर 2012 में 12,601 हो गई। पिछली जनगणना के अनुसार, 2011 में 58.7 प्रतिशत परिवार बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले रहे थे जबकि 2001 में यह संख्या मात्र 35.5 प्रतिशत थी। शाखा लाइसेंसीकरण नीति के उदारीकरण और वित्तीय समावेशन के प्रयासों के कारण नई खोली गई कुल शाखाओं में ग्रामीण और अर्द्ध शहरी शाखाओं का हिस्सा बढ़कर 2011-12 में 69.8 प्रतिशत हो गया जो कि 2004-05 में मात्र 23.2 प्रतिशत था। नई खोली गई शाखाओं में अब तक बैंक रहित रहे केंद्रों का हिस्सा 2011-12 के दौरान लगभग

20 प्रतिशत था। देश में बैंक रहित केंद्रों की भारी मात्रा को देखते हुए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है और यह प्रयास किए जा रहे हैं। वित्तीय समावेशन बढ़ाने के प्रयास के रूप में रिज़र्व बैंक बैंकों को प्रोत्साहित कर रहा है कि वे बिजनेस कारेसपांडेंट (बीसी) मॉडल के माध्यम से, जिसमें बीसी के रूप में कार्य करने के लिए "लाभ के लिए कार्यरत संस्थाओं" को अनुमति दी गई है, और बैंकिंग सेवाएं देने के लिए मोबाइल प्रौद्योगिकी सहित उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ लेकर बैंकिंग की पहुंच बढ़ाएं। इस संबंध में कुछ प्रगति हुई है किंतु एक ठोस वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभी भी बहुत कार्य किया जाना है। वित्तीय समावेशन का दायरा कुछ उन्नत और विकासशील देशों की तुलना में अधिक है। वित्तीय समावेशन के देशवार विश्लेषण में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि प्रति 0.1 मिलियन वयस्कों के लिए हमारे यहां 10.64 शाखाएं और 8.90 एटीएम हैं जबकि ब्राजील में यह संख्या क्रमश: 46.15 शाखाएं और 119.63 एटीएम है। वित्तीय रूप से अलग रह गई इस विशाल जनसंख्या में हमारे लिए अनेक अवसर उपलब्ध हैं।

13. मात्र संख्या के संदर्भ में हुई वृद्धि का तब तक कोई अर्थ नहीं होगा जब तब वह समाज के प्रत्येक हिस्से - दुर्बल, अलाभप्राप्त और अलग रहे लोगों तक न पहुंच जाए। शाखा नेटवर्क को ग्रामीण भारत तक पहुंचाने में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। किंतु यह देखा गया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता जिससे रिज़र्व बैंक बैंकों को इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता आया है। ऐसी सामाजिक सुरक्षा के अनेक लाभार्थी 2,000 से कम जनसंख्या वाले गांवों में रहते हैं, अत: रिज़र्व बैंक इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण का लाभ सभी गांवों तक पुहंचाने पर बल दे रहा है। अत: एसएलबीसी के आयोजक बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 2000 से कम जनसंख्या वाले सभी बैंक रहित गांवों को कवर करते हुए एक रोडमैप बनाएं और इन्हें समयबद्ध रूप से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न बैंकों के बीच आबंटित करें। इसके अलावा, बैंकों के लिए यह भी आवश्यक है कि जिन गांवों में पक्की शाखाएं नहीं हैं वहां इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण सेवाओं को शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक गांव में एक बीसी टच पॉईंट उपलब्ध कराएं। बीसी गांवों में नियमित रूप से जाकर इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण के लाभार्थियों को उनके आवास पर भी सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं ताकि वहां के लोगों को पक्की शाखाओं और बीसी के संयुक्त नेटवर्क के माध्यम से सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं मिलना सुनिश्चित हो सके। हमने अपने " इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण के कार्यान्वयन और वित्तीय समावेशन योजना के साथ इसके अनुरूपण पर परिचालनात्मक दिशानिर्देश" में एक जिला-अनेक बैंक-एक प्रमुख बैंक मॉडल की सिफारिश भी की है जिससे इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण को सरल और चरणबद्ध तरीके से शीघ्र लागू किया जा सके। बैंक इस कार्य को मात्र सीएसआर गतिविधि के रूप में न देखकर इसे बेहतर और लाभदायक अवसर के रूप में देखें और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरे प्रयास करें। इसी प्रकार, बैंकों को चाहिए कि वे आधारभूत बचत बैंक जमा खाते खोलने जैसी बैंकिंग सेवाएं देने का कार्य विनियामकीय भार न समझते हुए इसे संभाव्य कारोबार के अवसर के रूप में लें। इस बात को शीघ्र समझ लेना स्वयं बैंकों के ही हित में है कि वित्तीय रूप से अलग रह गए केंद्रों में संकेंद्रित लोगों में उनकी भावी वृद्धि और लाभप्रदता की अपार संभावनाएं हैं और इससे अर्थव्यवस्था भी तेजी के पथ पर आ सकती है।

बुनियादी सुविधा का वित्तपोषण - उच्च संभावना

14. उत्प्रेरक वृद्धि बुनियादी सुविधाओं के विकास पर बल देती है जिनमें कुशल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, पथ, सार्वजनिक उपयोग की सुविधाएं, आवास, शैक्षिक संस्थाएं, लोकोमोटिव प्लांट, बंदरगाह, कंटेनर टर्मिनल आदि शामिल होते हैं और यह किसी भी विकासशील देश का मुख्य आधार होते हैं। बढ़ती अर्थव्यवस्था की सहायता के लिए बुनियादी सुविधाओं की बढ़ती आवश्यकताओं के लिए विशाल निवेश आवश्यक होता है। मॅककिन्से अनुमान के अनुसार प्रति वर्ष हमें 700-900 मिलियन स्क्वेअर मीटर आवासी और वाणिज्यिक स्थान, 350-400 कि.मी. मेट्रो और सब वे तथा 19,000-25,000 कि.मी. मार्ग का निर्माण करना होगा। यह कार्य अति विशाल है और बैंको के लिए भी यह उतना ही बढ़ा अवसर है। 12 वीं योजना के एप्रोच पेपर के अनुमान के अनुसार बुनियादी सुविधा निवेश आधार वर्ष (2011-12) के जीडीपी के लगभग 8.0 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में जीडीपी के लगभग 10.0 प्रतिशत हो जाएगा। बारहवीं योजना अवधि के दौरान बुनियादी सुविधाओं में कुल निवेश ₹45 लाख करोड़ रुपए या 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर होगा।

15. निवेश के इस स्तर के वित्तपोषण के लिए सरकारी क्षेत्र से अधिक परिव्यय आवश्यक होगा किंतु इसके साथ निजी निवेश में अनुपात से अधिक वृद्धि होनी चाहिए। ग्यारहवीं योजना में निजी और पीपीपी निवेश बुनियादी सुविधाओं के कुल निवेश के 30.0 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है। बारहवीं योजना में यह हिस्सा बढ़कर 50.0 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। पेंशन और भविष्य निर्वाह निधि का व्यापक नकदी प्रवाह बुनियादी सुविधा ऋण निधि की ओर लाने के लिए निवेश मानदंडों में संशोधन करने के सरकार के प्रस्ताव से भी बुनियादी सुविधा परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक निधीयन का विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध हो जाएगा। बुनियादी सुविधाओं का निधीयन अब तक कोई विशेष बाधा नहीं रहा है और बुनियादी सुविधा ऋण उद्योगों को प्राप्त कुल बैंक ऋण का लगभग एक तिहाई भाग रहा है। किंतु इस संबंध में कुछ अन्य बाधाएं रही हैं जैसे कि नीति की घोषणा, पर्यावरणीय क्लियरेंस, भूमि अधिग्रहण, अनुमति आदि में में विलंब होना जिससे परियोजना में विलंब और लागत वृद्धि होती है। जहां सरकार को इन बाधाओं को हटाना होगा और बुनियादी सुविधा क्षेत्र में निवेश को सरल बनाना होगा, वहीं बुनियादी सुविधा परियोजनाओं की लंबी प्रारंभिक अवधि को ध्यान में रखकर बैंकों को ऋण आकलन, निगरानी और जोखिम प्रबंधन कौशल की क्षमता बढ़ानी होगी। इससे एनपीए की स्थिति नियंत्रण में रखते हुए इस क्षेत्र की निधीयन आवश्यकता पूरी होना सुनिश्चित होगा।

बैंकों के समक्ष चुनौतियां

उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता

16. 2011 और 2012 में अर्थव्यवस्था में सामान्य मंदी और उच्च ब्याज दर वातावरण के कारण बैंकों के निष्पादन में भी कुछ नरमी रही। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) के तुलनपत्रों ने 2010-11 के 19.2 प्रतिशत की तुलना में 2011-12 में 15.5 प्रतिशत की कम वृद्धि दर्ज की जिसमें ऋण वृद्धि में गिरावट आई थी। जमाराशियों की लागत वृद्धि से बैंकों का निवल लाभ प्रभावित हुआ जो कि पिछले वर्ष के 23.2 प्रतिशत की तुलना में 16.1 प्रतिशत की कम दर से बढ़ा। जमाराशि पर व्यय हुआ ब्याज और सावधी जमा की उच्च लागत के कारण बैंकों की ब्याज लागत में वृद्धि हुई। बैंकों की निवल ब्याज मार्जिन पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कम हो गई। किंतु बैंकों की लाभप्रदता के विश्लेषण से पता चलता है कि विदेशी बैंकों की लाभप्रदता अन्य बैंक समूहों की तुलना में अधिक थी। बैंकिंग प्रणाली की कुल आस्तियों में लगभग 7 प्रतिशत हिस्से के बावजूद एससीबी के लाभ में उनका हिस्सा लगभग 12 प्रतिशत था। डू पॉन्ट विश्लेषण से पता चलता है कि बैंक समूहों के बीच विदेशी बैंकों द्वारा आस्तियों पर उच्च प्रतिलाभ प्राप्त करने का कारण उनका बेहतर आस्ति उपयोग था हालांकि उनका आस्ति-परिचालन व्यय अनुपात अन्य बैंक समूहों की तुलना में अधिक था। उनकी उच्च लाभप्रदता का कारण बेहतर निधि प्रबंधन प्रथाएं हो सकती हैं। इस क्षेत्र में भारतीय बैंकों द्वारा सुधार करने की जरूरत है।

17. एनपीए के उच्च स्तर के कारण 2012-13 के दौरान एससीबी की लाभप्रदता पर दबाव बढ़ेगा। बैंकिंग प्रणाली का सकल एनपीए मार्च 2011 के 2.36 प्रतिशत से बढ़कर जून 2012 में 3.25 प्रतिशत हो गया। सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में पुनर्संरचित मानक खाते 2009 के 2.7 प्रतिशत से दोगुने होकर जून 2012 के अंत में 5.4 प्रतिशत हो गए जिसमें कुछ क्षेत्रों में पुनर्संरचना में काफी वृद्धि हुई थी। आंकड़ों से पता चलता है कि पुनर्संरचना का सहारा मुख्यत: औद्योगिक क्षेत्र और विशेष रूप से कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्यमों जैसे छोटे उधार खातों के विपरीत बड़े उद्योगों के खातों के मामले में लिया जाता है। एनपीए का निरंतर उच्च स्तर और पुनर्संरचित खातों में वृद्धि से बैंकों की उधार दर घटाने की क्षमता बाधित होती है जिससे अंतत: ईमानदार उधारकर्ताओं का नुकसान होता है। कार्पोरेट्स के लिए यह आवश्यक है कि वे नई संभावनाओं की खोज करें और प्रौद्योगिकी अपनाएं ताकि उनकी उत्पादकता और कौशन में सुधार हो जिससे उनकी लागत कम हो सके, वे प्रतियोगिता में बने रह सकें और उधारकर्ताओं के प्रति अपने दायित्व पूरे कर सकें। बैंकों को चाहिए कि वे बेहतर ऋण आकलन, उधारकर्ता खातों की सूक्ष्म निगरानी, बैंकों के बीच अधिक सूचना बंटवारा और पुनर्संरचना से पहले व्यापक सक्षमता अध्ययन जैसी बेहतर जोखिम प्रबंधन प्रथाएं अपनाकर आस्ति गुणवत्ता की गिरावट को रोकने के प्रयास करें। जहां एनपीए/आस्तियों की पुनर्संरचना से पूर्णत: बचा नहीं जा सकता, वहीं उन्हें प्रभावी रूप से कम करने की आवश्यकता है ताकि बैंकों के उधार देने योग्य स्रोतों को अधिकतम किया जा सके। भारिबैं ने अपनी ओर से बैंकों के लिए अनिवार्य किया है कि वे सूचना के बंटवारे के लिए प्रभावी प्रणाली दिसंबर 2012 तक स्थापित कर लें और नए या वर्तमान

उधारकर्ताओं को सूचना प्राप्त/शेयरिंग करने के बाद ही तदर्थ ऋण दें/ऋण का नवींकरण करें।

पोषक वातावरण की कमी

18. डुईंग बिजनेस रैंकिंन्गस 2013 के अनुसार "ईज ऑफ डुईंग बिजनेस" में देशों की वैश्विक अनुसूची में 185 देशों में भारत की रैंक 132 पर बहुत नीचे थी जो कि चीन से 41 स्थान से नीचे, श्रीलंका से 51 स्थान नीचे और ताईवान से 116 स्थान नीचे थी। पोषक आर्थिक वातावरण होने पर ही विस्फोटक संवृद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए सरकारी नीतियां शीघ्र क्लियरेंस वाली होनी चाहिए जिससे कारोबार और दीर्घावधि निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। सरकारी वित्त की स्थिरता के लिए और राजकोषीय घाटे को उचित स्तर के भीतर रखने के लिए हाल ही में कुछ कदमों की घोषणा की गई है।

19. सरकार ने उपलब्ध प्रौद्योगिकी और विश्व में उपलब्ध पूंजी का लाभ प्राप्त करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सार्वजनिक निवेश और सार्वजनिक-निजी सहभागिता को प्रोत्साहन देने के लिए भी कुछ कदम उठाए हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि विस्फोटक संवृद्धि की प्राप्ति के लिए यह अनिवार्य है कि समष्टिआर्थिक वातावरण में स्थिरता आए, मुद्रास्फीति और इसकी आशंकाएं सुविधाजनक स्तर तक नीचे आए और दोहरा घाटा नियंत्रित रहे। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से प्रभावी परिवर्तन होना आवश्यक है।

अवसरों की प्रचुरता

ग्राहक की केंद्रियता

20. प्रत्येक चुनौती एक अवसर भी होती है। बोस्टन परामर्शी समूह अध्ययन "भारतीय बैंकिंग 2020 - दशकों का आश्वासन सत्य हुआ" के अनुसार ₹90,000 से ₹2.00 वार्षिक की हाउसहोल्ड आय वाले मध्य वर्ग से नीचे वाला आय समूह सबसे बड़ा ग्राहक समूह होगा जिसकी संख्या 2010 के 75 मिलियन हाउसहोल्ड से बढ़कर 2020 में 120 मिलियन होने की संभावना है जि कि "अगला बिलियन" है। ग्राहकों का यह वर्ग वहनीय, कम लागत की बैंकिंग सेवाओं की मांग करेगा। बैंकों के सामने बैंक शाखाओं/एटीएम/बीसी मॉडल के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को इस संभाव्य ग्राहक वर्ग तक पहुंचाकर इस अवसर का लाभ लेने की चुनौती है। बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे ग्राहक केंद्रित उत्पाद और सेवाएं विकसित करें। इनका मूल्य वहनीय और उपयुक्त होना चाहिए। मोबाइल सेवाओं सहित प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग से बैंकिंग में क्रांति आ जाएगी। मोबाइल बैंकिंग में अपार संभावनाएं हैं। बीसीजी अध्ययन का अनुमान है कि यदि 25-30 प्रतिशत मोबाइल उपयोगकर्ता भी जीपीआरएस/3जी को एक्टिवेट करते हैं तो 250 मिलियन से 300 मिलियन ग्राहक मोबाइल पर बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। भारतीय बैंकिंग उद्योग को बैंकिंग लेनदेन के लिए कुशल और कम लागत वाली संरचना बनानी होगी। भविष्य में ग्राहक संतुष्टि ही सफलता की कुंजी होगी जो सफल बैंकों को औरों से अलग करेगी।

लक्ष्य बड़ा रखें, छोटी बातों पर ध्यान दें

21. यदि हमें तेज संवृद्धि प्राप्त करनी है तो बैंकों को एसएमई, कृषि और खुदरा क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना होगा। यह जीवन का तथ्य है कि बड़ी कंपनियों को बैंकिंग क्षेत्र से आसानी से काफी ऋण मिल जाता है किंतु एनपीए/पुनर्निधारित खातों में भी उनका हिस्सा बहुत अधिक होता है। इसके विपरीत, छोटे उधारकर्ता/एमएसएमई को बैंकों से ऋण मिलने में काफी कठिनाइयां आती हैं क्योंकि उनमें अधिक जोखिम मानी जाती है और उनके ऋण की मात्रा भी कम होती है। इस संदर्भ में इस बात को समझने की आवश्यकता है कि इस क्षेत्र में कमजोरी का कारण वित्त की कमी और बैंकों द्वारा उचित स्तर पर इनकी पर्याप्त सहायता न करना है। बैंकों को यह समझना चाहिए कि पर्याप्त आकलन, उचित मूल्यन से और एमएसएमई को उचित सहायता देने से बैंकों की बॉटम लाइन में वृद्धि के संदर्भ में यह क्षेत्र बड़ा परिवर्तन ला सकता है।

22. बैंकों को ऐसे कारोबारी मॉडल और सुपुर्दगी माध्यमों को विकसित करना होगा जो कि कृषि/खुदरा/एसएमई क्षेत्र को मिलने वाले ऋण की लागत को कम करेंगे। यदि बैंक इस ग्राहक वर्ग के लिए अनुरूप और कम लागत वाले उत्पाद और सेवाएं और साथ ही इन क्षेत्रों को सहयोग उपलब्ध कराएं तो हम तेज संवृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। एनपीए में वृद्धि के भय के आधार पर इन क्षेत्रों को समय पर और पर्याप्त ऋण मिलने से वंचित नहीं किया जा सकता। ये क्षेत्र बैंकों के कारोबारी अवसरों में वृद्धि करने के अलावा रोजगार और बचत में वृद्धि में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं और जीडीपी वृद्धि में भी सहायता कर सकते हैं।

23. नए कारोबारी विचारों को सामने लाने और उन्हें प्रोत्साहन देने और उन्हें वास्तविक स्वरूप देने की भी आवश्यकता है। यदि रीड गॅरेट हॉफमन और पीटर थील जैसे सद्भावी निवेशकों ने

मार्क जुकरबर्ग को वित्तीय सहायता नहीं दी होती तो फेसबुक एक वास्तविकता नहीं बनी होती। बीसीजी भारत अध्ययन के अनुसार भारत में 190,000 करोड़पति हैं किंतु लगभग 500 ही सद्भावी करोड़पति हैं। भारत में एचएनआई स्थावर संपदा में निवेश को तरजीह देते हैं। साहस पूंजी निधि कुछ हद तक प्रारंभिक रूप से निधि उपलब्ध कराती है, किंतु एक ऐसी सक्षम इकोप्रणाली के विकास के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है जिसमें उन नए विचारों को बढ़ावा दिया जाएगा जो कि रोजगार और धन की उत्पत्ति में सहायक होंगे। बैंक ऐसे नवोन्मेशों के लिए निधि उपलब्ध कराने पर विचार कर सकते हैं।

व्यवहारात्मक परिवर्तन

24. सफलता के लिए यह आवश्यक है कि बैंक अपने कारोबारी रवैये में परिवर्तन लाएं, नवोन्मेष की शक्ति को बढ़ाएं, पिरामिड के नीचले स्तर में उपलब्ध व्यापक संभावना को पहचाने और वहां तक पहुंच बनाएं। बैंकों को ग्राहकों को शिक्षा देकर और इको प्रणाली को समझकर, जिसमें छोटे कारोबार और कृषि के परिचालनों की संवृद्धि तथा विकास होता है, वित्तीय साक्षरता में और आगे बढ़ना होगा। उन्हें वित्तीय टिकाऊ कारोबार के लिए साझेदारी में कार्य करना सीखना होगा।

25. "मैं भी" पद्धति से भीड़ के पीछे चलकर बड़ी कंपनियों के वित्तपोषण को सुरक्षित मानने मे ही सफलता नहीं होती। सफलता का अर्थ सोच में बदलाव, नए मार्गों की खोज, ग्राहक को सर्वोच्च स्थान देने और प्रौद्योगिकी का लाभ लेने में है। इसके लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन और जोखिम प्रबंधन की क्षमता से युक्त प्रतिबद्ध कार्यबल आवश्यक होता है। इसके लिए यह जरूरी है कि सरकारी क्षेत्र में मौजूदा कार्यबल का कौशल बढ़ाया जाए और प्रतिभा को प्राप्त किया जाए और बनाए रखा जाए क्योंकि अगले कुछ वर्षों में सेवानिवृत्त होने वालों की संख्या काफी अधिक है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को तेज और प्रभावी निर्णय लेने के लिए निष्पादन प्रबंधन, सोच में बदलाव और कर्मचारियों को अधिकार देने पर अधिक ध्यान देना होगा। यदि सरकारी क्षेत्र के बैंक छोटे किंतु तेज गति वाले निजी क्षेत्र/विदेशी बैंकों की तुलना में प्रतिस्पर्धी लाभ बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए बैंकिंग क्षेत्र में और विशेष रूप से इसके लिए बैंकिंग क्षेत्र में और विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सांस्कृतिक क्रांति की जरूरत है।

विनियामकीय/पर्यवेक्षीय वातावरण

26. मजबूत संवृद्धि प्राप्त करने की एक अनिवार्य पूर्व अपेक्षा वित्तीय स्थिरता है जिसके लिए मजबूत विनियम और पर्यवेक्षण जरूरी होता है। विनियामकों और पर्यवेक्षकों को वित्तीय प्रणाली के बदलते माहौल का ज्ञान होना चाहिए और बैंकों की कार्य प्रणाली में बदलाव, नए उत्पाद और सेवाएं, जोखिम और निवारकों के प्रति उन्हें सचेत होना चाहिए। उनका ध्यान चारों ओर होना चाहिए ताकि वे वित्तीय प्रणाली की किसी समस्या के शिकार न हो जाए जो कि उनके लिए वित्तीय सुनामी सिद्ध हो सकती है। हाल के सब-प्राईम संकट से हुई वित्तीय और मानव संसाधन की क्षति को देखते हुए हम इसकी पुनरावृत्ति को नहीं सह सकते। इसलिए संवृद्धि के लिए पोषक एक मजबूत वित्तीय प्रणाली और वातावरण बनाने के लिए एक मजबूत पर्यवेक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक में हम पर्यवेक्षी प्रणाली और बैंकों के पर्यवेक्षण के तरीके पर ध्यान दे रहे हैं। इस प्रयोजनार्थ गठित उच्च स्तरीय स्टीयरिंग समिति की सिफारिशों के आधार पर हमने बैंकों के पर्यवेक्षण के संदर्भ में कैमल लेनदेन आदारित दृष्टिकोण से निकलकर जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाने की पहल की है। उच्च स्तरीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष के रूप में मेरे साथ हुई चर्चा और अन्य अवसरों पर बैंकों के प्रबंधन के साथ हुई चर्चा के आधार पर मेरा आकलन यह है कि अधिकतर बैंकों के पास उनकी कार्यवार लागत और लाभ की स्पष्ट धारणा नहीं है। वस्तुत: यह एक पहेली ही है कि बैंक जोखिम संबंधी कार्य/कारोबारी धारणाओं के अभाव में अपना जोखिम प्रबंधन किस प्रकार करते हैं?

27. इस पृष्ठभूमि में, पहले कदम के रूप में हमने बैंकों को सूचित किया है कि वे अपने जोखिम प्रबंधन की संरचना, संस्कृति, प्रथाएं और ऐसी ही अन्य संबंधित प्रक्रियाओं की पुन: समीक्षा करें और जोखिम आधारित पर्यवेक्षण लागू करने के लाभ के रूप में पहचानी गई कुछ अनिवार्य आवश्यकताओं के प्रति उन्हें बेंचमार्क बनाएं। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे जोखिम आधारित पर्यवेक्षण की ओर सरलता से बढ़ने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली, एमआईएस आदि के लिए अपेक्षित कौशल के संबंध में अपनी मानव संसाधन क्षमताओं का उन्नयन करें। आरबीएस पर जोखिम प्रोफाईल टेंप्लेट्स और दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने पर रिज़र्व बैंक बैंकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं

का आयोजन भी करेगा। इस बीच बैंकों के सामने उनकी एमआईएस क्षमताओं के उन्नयन, उनकी अंतरण मूल्यन नीतियों में सुधार, लेनदेन/गतिविधि वार लागत नापने, जोखिम-प्रतिलाभ समझौते का विकास, उत्पादों और सेवाओं के जोखिम आधारित मूल्यन के लिए और देयताओं के अविभेदकारी मूल्यन के लिए प्रभावी और पारदर्शी संरचना बनाने की चुनौती होगी।

समापन

28. समापन के तौर पर मैं कुछ मुख्य बातों का पुन: स्मरण करना चाहूंगा:

- पहली और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि केंद्र, राज्य, संस्था, निजी आदि सभी स्तरों पर अभिशासन के मानदंडों में सुधार किया जाए। सार्वजनिक जीवन और हमारे व्यवहार में ईमानदारी वह प्रमुख घटक है जो हम सब को एकसूत्रता में बांधे रखती है। तेज वृद्धि के प्रति सार्वजनिक मत/जागरूकता बनानी जरूरी है जो कि हमारे लिए आवश्यक परिवर्तन की मुख्य प्रेरक बनेगी। इसका समाधान आंदोलन न तो है और न ही कभी हो सकता है।
- बैंकिंग क्षेत्र को वास्तविक क्षेत्र से मजबूत संबंध विकसित करना होगा ताकि स्थिर और मजबूत संवृद्धि सुनिश्चित की जा सके। इसमें बैंकिंग परिचालन के सभी पहलू कवर होने चाहिए जिससे आस्ति मूल्य की अस्थायी वृद्धि संबंधी प्रणालीगत जोखिम से बचा जा सकता है।
- हम अपनी आंतरिक क्षमताओं को पहले परख चुके हैं। अब हमें अपनी मुख्य शक्ति पर ध्यान देने और उन बाधाओं को हटाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो कि हमारी संवृद्धि को रोकती हैं। हमें सामूहिक रूप से कड़ी मेहनत करके अपनी उत्पादकता और कौशल में वृद्धि करनी चाहिए। अपनी उच्च संवृद्धियुक्त अर्थव्यवस्था का लाभ न ले सकने का कोई कारण नहीं है। हम सभी भागीदारों को अपनी अर्थव्यवस्था को उच्च वृद्धि पथ पर ले जाने और भारत को एक ऐसी सक्रिय अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए जिसमें समावेशक वृद्धि का लाड़ व्यापक और गहन हो तथा इसका लाभ सभी को और विशेष रूप से निम्नतम पायदान के लोगों को भी मिले। हमारे सामूहिक प्रयास इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

29. मुझे इस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने और इस सम्मेलन के विषय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर देने के लिए एसोचॅम को पुन: धन्यवाद देता हूं। मेरा विश्वास है कि इसके बाद होने वाले तकनीकी सत्रों में वित्तीय समावेशन, सुधारे और उभरते विनियामक ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि उत्पादकता, नवोन्मेष और सुधारों के साथ ही वित्तीय क्षेत्र और वास्तविक क्षेत्र के बीच संबंध की आवश्यकता, जिस पर मैं पहले ही बोल चुका हूं, पर आगामी सत्रों में सारगर्भित चर्चा होगी।

मुझे आशा है कि आज की चर्चा से इस संबंध में एक नया विचार सामने आएगा कि भारतीय बैंकिंग की क्षमता का लाभ कैसे लिया जाए और अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की सहायता के लिए तेज संवृद्धि को कैसे प्राप्त किया जाए जिससे यह उच्च संवृद्धि पथ पर बढ़ सके। धन्यवाद।

संदर्भ:

1. भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति की रिपोर्ट 2011-12.

2. इंडियाज अर्बन अवेकनिंग: बिल्डिंग इन्क्लूजीव सिटीज, सस्टेनिंग इकोनोमिक ग्रोथ - मॅक किन्से ग्लोबल इन्स्ट्यूट, अप्रैल 2010.

3. डूईंग बिजनेस 2013 - आईएफसी ऐंड वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट.

4. तेज, मजबूत और अधिक समावेशक संवृद्धि - बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) का दृष्टिकोण.

5. इंडियन बैंकिंग 2020 - मेकिंग दि डिकेड्स प्रॉमसि कम ट्रू - बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप.

6. बिजनेस स्टैडर्ड, 18 अगस्त 2011 - इंडिया टू बी 5.6 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर इकोनोमी बाय 2020: दून ऐंड ब्रॅडस्ट्रिट.

7. बिजनेस वर्ल्ड इश्यू 19 नवंबर 2012 - वेयर आर दि एंजल्स?